भारत सरकार

संचार मंत्रालय

दूरसंचार विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 2989

उत्तर देने की तारीख 20 दिसबंर, 2023

बीएसएनएल मोबाइल टॉवर

2989. श्री बी.वाई. राघवेन्द्रः

क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि 4जी संतृप्ति परियोजना के अंतर्गत शिवमोगा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के लिए बीएसएनएल मोबाइल टावरों को मंजूरी दी गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और निर्माण कार्य पूरा करने की समय-सीमा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस बात पर ध्यान दिया है कि कार्य की प्रगति बहुत धीमी है और यह समय-सीमा में पूरा नहीं हो पाएगी;

(घ) क्या सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए कोई कदम उठा रही है कि यह कार्य निविदा कार्यक्रम के अनुसार पूरा हो जाए; और

(ड.) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

संचार राज्य मंत्री

(श्री देवुसिंह चौहान)

(क) से (ड़) देश में पिछले 10 वर्षो में दूरसंचार कनेक्टिविटी में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। बीटीएस (बेस ट्रांसीवर स्टेशन) की कुल संख्या मार्च- 2014 में 6.49 लाख से बढ़कर मार्च-2023 में 25.42 लाख हो गई है। कुल मोबाइल उपभोक्ताओं की संख्या मार्च 2014 में 90.45 करोड़ से बढ़कर अगस्त 2023 में 114.84 करोड़ हो गई है। इंटरनेट उपभोक्ताओं की संख्या मार्च-2014 में 25.15 करोड़ से बढ़ कर मार्च- 2023 में 88.12 करोड़ हो गए हैं।

सरकार ने ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाने सहित दूरसंचार अवसंरचना के तीव्र रॉलआउट के लिए कई पहलें की है। इन पहलों में गतिशक्ति संचार पोर्टल को लॉन्च करना और समय-समय पर यथा संशोधित भारतीय तार मार्ग का अधिकार नियमावली, 2016 जारी करना शामिल है। इसके परिणामस्वरूप देश में पिछले 10 वर्षो में ऑप्टिकल फाइबर केबल कनेक्टिविटी में काफी सुधार हुआ है।

देश के सेवा से वंचित गांवों में दूरसंचार कनेक्टिविटी उपलब्ध कराने के लिए सरकार ने कई स्कीमें शुरू की है। सरकार ने 41,331 करोड़ रूपये से अधिक की लागत से 54,000 से अधिक गांवों को कनेक्टिविटी उपलब्ध कराने के लिए देश के सेवा से वंचित क्षेत्रों में 41,160 टावर लगाने की योजना बनाई है।

दिनांक 31.10.2023 की स्थिति के अनुसार सार्वभौमिक सेवा दायित्व निधि (यूएसओएफ) के अन्तर्गत 7,535 गांवों को कवर करते हुए विभिन्न स्कीमों के तहत देश में कुल 6,394 मोबाइल टावर पहले ही चालू किए जा चुके हैं।

*****